उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
मुख्यमंत्री आवास, न्यू कैंट रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 05 सितम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–05(09/16)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को कैम्प कार्यालय मुख्यमंत्री आवास में इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड के साथ डेवेलपमेंट रोड मैप ऑफ उत्तराखण्ड के सम्बन्ध मे बैठक की गयी। बैठक में, उत्तराखण्ड के विकास के लिये बहुत से बिन्दुओं पर चर्चा की गयी साथ ही इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से कई सुझाव दिये गए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य को विकसित करने के लिये हमें राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को विकसित करना होगा। हमें इसके लिये जिला स्तर पर अध्ययन कराने की आवश्यकता है जिससे यह ज्ञात हो सके कि इस क्षेत्र में क्या कार्य किया जा सकता है। यह जानकारी प्राप्त होने के बाद हम वहाँ के युवा को प्रशिक्षित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा दिये गए कुछ सुझाव बहुत ही अच्छे हैं जिन्हें अमल में लाया जा सकता है। राज्य का उद्योग क्षेत्र इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके लिये इंडस्ट्री एसोसिएशन द्वारा एक डिमांड सर्वे कराया जाए, ताकि हमें क्षेत्रवार डिमांड का पता चल सके। जिसके अनुरूप जिलेवार पॉलिसी तैयार की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रत्येक माह की आखिरी कैबिनेट के बाद उद्योग एसोसिएशन के साथ भी बैठक रखी जाए ताकि उस बैठक में सभी मंत्रीगण भाग ले सकें। बैंकों के साथ समन्वय बनाने के लिये जिला स्तर पर एक समिति गठित की जाए। उद्योगों को आमंत्रित करने के लिये कॉमन फैसिलिटी सेंटर विकसित किये जाएं ताकि उद्योगों को सभी सुविधाएँ एक जगह पर मुहैया हो सकें। मुख्यमंत्री ने एक लैंड बैंक तैयार करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जिलों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट का विकास किया जाना चाहिए।

इंडस्ट्री एसोसिएशन के सुझाव की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी योग्यता एवं रूचि के अनुसार वोकेशनल ट्रेनिंग उपलब्ध करायी जा सकती है। इसके लिये शिक्षण संस्थानों का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही, इसके लिये वर्चुअल क्लासरूम्स का प्रयोग भी किया जा सकता है। राज्य में रक्षा उपकरणों के निर्माण हेतु डिफेन्स प्रोडक्ट पार्क स्थापित किये जा सकते हैं।

कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि हमें प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करके ही राज्य का विकास किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी एक गाँव से एक व्यक्ति का चयनित करके, उस व्यक्ति को उस क्षेत्र के अनुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा सके। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि यदि इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन द्वारा निर्माण सामग्री में मेंटरशिप उपलब्ध कराता है तो एमएसएमई इसमें फैसिलिटेटर की भूमिका निभा सकता है।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री डी. सेंथिल पांडियन, अपर सचिव श्री पंकज कुमार पाण्डेय एवं अध्यक्ष इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड श्री पंकज गुप्ता भी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

देहरादून 05 सितम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–04(09/15)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में विगत 8 अगस्त 2017 को विभिन्न शैक्षणिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई वार्ता के क्रम में 16 अगस्त 2017 को जारी कार्यवृत्त के अनुसार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षक संघों की कुल 22 मांगों में से 11 मांगे ऐसी है, जिनमें निदेशालय अथवा शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है।

सचिव विद्यालयी शिक्षा श्री चन्द्रशेखर भट्ट ने बताया कि उपरोक्त 11 मांगों से लगभग 5 प्रकरणों की कार्यवाही निदेशालय स्तर एवं 6 प्रकरणों पर शासन स्तर पर विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार राजकीय शिक्षक संघ की कुल 7 मांगों में से 6 मांगों पर कार्यवाही किए जाने की सहमति मुख्यमंत्री द्वारा दी गई थी। जिनमें से 2 प्रकरणों में निदेशालय स्तर एवं 4 प्रकरण में शासन स्तर पर कार्यवाही प्रगति में है।

माध्यमिक शिक्षक संघ की 7 मांगों में से कुल 3 मांगों में कार्यवाही प्रतीक्षित हैं। जिनमें से 1 निदेशालय स्तर एवं 2 शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। शिक्षा विभाग द्वारा कतिपय प्रकरणों में वित्त विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। साथ ही कुछ मामलों को न्याय विभाग की सहमति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक महत्वपूर्ण प्रकरण कोटद्वार विधानसभा उपचुनाव के कारण वर्ष 2005 में नियुक्ति से वंचित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने से संबंधित है। जो कि वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकांश प्रकरणों में शिक्षा निदेशालय से प्राप्त प्रस्तावों पर शासन में पत्रावलियां उच्चानुमोदन हेतु गतिमान है। विद्यालयों के वर्गीकरण एवं कोटिकरण की विसंगतियों के निराकरण हेतु गठित समिति द्वारा इस दिशा में पर्याप्त प्रगति कर ली गई है। प्रारंभिक शिक्षा में अध्ययनरत छात्रों की क्रीडा प्रतियोगिता हेतु निर्धारित धनराशि रुपये 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किए जाने से संबंधित पत्रावली उच्चानुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश विकल्पधारी शिक्षकों को कार्यमुक्त किए जाने विषयक प्रस्ताव भी उच्चानुमोदन हेतु बढाये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड शासन का शिक्षक संघ की विधिसम्मत मांगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

खुमाड/सल्ट/देहरादून 05 सितम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(09/15)**

सल्ट को उनके महान त्याग और बलिदान के आधार पर कुमाऊँ की बारदोली की संज्ञा दिलवाना समस्त सल्ट निवासियों की सुसंगठित एवं सुदृढ़ शक्ति का परिणाम है। भारत माता को स्वतन्त्र कराने के लिए देश में सर्वत्र बलिदान एवं आहुतियॉ हुई पर इतिहास प्रसिद्व बारदोली इसी क्षेत्र को कहा गया। यह बात मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को खुमाड़, सल्ट में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कही। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि देश की आजादी में हमारे शहीदों का अभूतपूर्व योगदान है, जिसे भुलाया नही जा सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को सल्ट के विधायक सुरेन्द्र सिंह जीना ने कुमाऊ की बारडोली नामक एक पुस्तक भेंट की। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट, विधायक श्री सुरेन्द्र जीना सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि 1942 की जनक्रान्ति का व्यापक असर पूरे देश के साथ–साथ सल्ट में भी पड़ा। सल्ट के कार्यकर्ताओं ने सभाओं द्वारा आजादी की घोषणा की तथा भारत छाडो नारे को बुलन्द किया। स्वतन्त्रता संग्राम में सल्ट का बलिदान सदा अविस्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम 2021 तक पूरे प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और शौचालय की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचायेंगे। इसके लिये प्रत्येक विभाग के लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। उन्होंने संस्थागत भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही और कहा कि कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जायेगा तो उसके खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिये 13 नये पर्यटन स्थलों को विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश की अधिकांश सड़कों को राष्ट्रीय राज्य मार्ग घोषित कर दिया गया है। हवाई सेवाओं को बढ़ावा देने के लिये जनपद के चौखुटिया में हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। चिन्यालीसैण, पिथौरागढ़ व पंतनगर हवाई अडडों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक पर्यटक उत्तराखण्ड में आ सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये 203 डाक्टरों का चयन कर लिया गया है, जिन्हें दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जायेगा। इसके साथ ही 250 आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र की सबसे गम्भीर समस्या पलायन की है। इसके लिये एक आयोग का गठन कर दिया गया है। जिसमें विषय विशेषज्ञों को रखा गया है, जो इस पर अध्ययन करेंगे। उन्होंने कहा कि 670 न्याय पंचायतों को विकसित कर वहां पर महिला समूह व महिलाओं को स्वालम्बी बनाने का कार्य किया जायेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने 313.46 लाख रू0 की लागत की 07 योजनाओं का शिलान्यास किया। जिनमें से राज्य योजना अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सल्ट में जाख से डांग से मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं सी0सी0 का कार्य लागत 51.42 लाख रू0, राज्य योजना के अन्तर्गत सल्ट में मुख्य मोटर मार्ग सैढमानुर तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य लागत 55.22 लाख रू0, विधानसभा क्षेत्र सल्ट–बरकिन्डा–मानिला डोटियाल मोटर मार्ग में मानिला से बिष्ट बाखली तक मार्ग का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य लागत 60.61 लाख रू0, बरकिन्डा–मानिला मोटर मार्ग से रतखाल बाजार मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं नाली निर्माण का कार्य लागत 19.36 लाख रू0, जमरिया गॉव तक रोड़ का सुधारीकरण एवं डामरीकरण का कार्य लागत 37.15 लाख रू0, सल्ट में मुख्य मोटर मार्ग से भौनादेवी मन्दिर सम्पर्क मार्ग का सुधारीकरण, डामरीकरण एवं डिफैक्ट कटिंग का कार्य लागत 44.93 लाख रू0 भौनडाडा से जामड़ी–जैखाल मोटर मार्ग के अवशेष भाग के डामरीकरण का कार्य लागत 44.77 लाख रू0 प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रानीखेत द्वारा राज्य योजना के अन्तर्गत इन कार्यों को किया जायेगा। इस अवसर पर उन्होंने हंसी ढुंगा, ढुगरकोट जिसमें 190 गांव लाभान्वित होगें उसके लिये पम्पिंग योजना की स्वीकृति प्रदान की।

इस अवसर पर उन्होंने पूर्व में हुई 14 घोषणायें जिनका शासनदेश पूर्व मे नहीं हुआ था उसका शासनादेश किये जाने की बात कही। जिनमें मानिला में मिनी स्टेडियम का निर्माण, ईको पार्क का निर्माण, झिमार पम्पिंग योजना, सल्ट बाजार में हाईटैक शौचालय का निर्माण, मानिला में रिवर राफ्टिंग का निर्माण, मरचूला में झील निर्माण, इनालू हेतु लिफ्ट निर्माण, सल्ट के पुराने मंदिरों का निर्माण, मेटला में पूल का निर्माण, हरड़ा से भिकियासैण की सड़क का नाम स्व0 गोपाल सिंह रावत के नाम से करने की घोषणा सहित अन्य योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने हिमालय बचाओं दिवस की सभी को प्रतिज्ञा दिलायी और कहा कि यह एक अच्छी पहल शुरू की गई है, इसमें हम सभी को सहयोग प्रदान करना होगा।

इस अवसर पर केन्दीय कपड़ा राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा ने शहीदों को श्रद्वाजंली देते हुए कहा कि सल्ट क्षेत्र वीरो की भूमि रही है। शहीदों को हमारी सच्ची श्रद्धाजंलि तभी सिद्ध होगी जब हम उनकी भावनाओं के अनुरूप क्षेत्र के विकास के लिए संगठित होकर कार्य करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की अनेक समस्याओं से भी अवगत कराया।

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भटट, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह चौहान, सल्ट के विधायक सुरेन्द्र जीना न भी अपने विचार रखते हुए कहा सल्ट के विकास के लिए सरकार पूर्णरूप से कटिबद्ध है। यहॉ का विकास सुनियोजित ढंग से करने के प्रयास किये जायेंगे।

नोट : जिला सूचना कार्यालय, अल्मोड़ा से प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर।

देहरादून 05 सितम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(09/14)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राजभवन में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित गवर्नस टीचर अवार्ड कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि समाज को नई दिशा दिखाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षक की भूमिका सबसे अलग होती है। आज आवश्यकता है कि छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए किताबी ज्ञान के अलावा पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त भी विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। गवर्नर्स अवार्ड में संस्कृत शिक्षकों को भी पहली बार पुरस्कार की श्रेणी में शामिल किये जाने पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि संस्कृत शिक्षा की मांग विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है। संस्कृत संस्कारों को प्रदान करने वाली एक सात्विक भाषा है। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति श्री एस.राधाकृष्णन को स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राधाकृष्णन ने 40 वर्ष तक एक शिक्षक के रूप में अपने कर्त्वव्यों का निर्वहन किया। उनकी वेशभूषा में भारतीय संस्कृति एवं परम्परा दिखती है। नव भारत निर्माण एवं युवा भारत की आधारशिला रखने वाले छात्रों के चरित्र निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज आवश्यकता है कि शिक्षक अपने ज्ञान के भण्डार में वृद्धि करते रहें। जिससे नव भारत निर्माण करने वाले युवाओं को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिले।

देहरादून 05 सितम्बर, 2017(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(09/13)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में शिक्षक दिवस के अवसर पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर से जुड़े लगभग 4000 शिक्षकों को सीधे संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों का आह्वान किया कि वो सकारात्मक रूख अपनाते हुए राज्य के विकास और विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को स्वाध्याय के प्रति प्रेरित करते हुए कहा कि एक शिक्षक के एक घण्टे के स्वाध्याय का परिणाम औसतन 160 घण्टे का अध्यापन होता है। उन्होने कहा कि शिक्षा रूपी अक्षय पात्र का संचालन शिक्षकों की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा सरकारी स्कूलों के प्रति अपेक्षाकृत कम रूझान पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा उत्तराखंड में प्रति बच्चे पर जो व्यय होता है वह देश में सबसे ज्यादा है। उन्होने कहा कि क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ अध्यापक होने के बाद भी सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास में कमी है। सरकारी शिक्षकों की सेवा शर्ते, वेतन इत्यादि भी प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होता है। प्राइवेट स्कूलों में जहां औसतन 25 बच्चों पर एक अध्यापक होता है, वहीं सरकारी स्कूलों में 12 बच्चों पर एक अध्यापक होता है। उन्होने राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों का आह्वान किया कि वे अपनी क्षमता एवं लगन से सरकारी विद्यालयों के प्रदर्शन को और बेहतर बनायें। उन्होने कहा कि राज्य में कुल मिलाकर 14985 प्राइमरी स्कूल और 5088 उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। इसके अतिरिक्त 2259 माध्यमिक स्कूल है। प्राइमरी स्कूलों में 4 लाख 88 हजार 833 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिनमें 2 लाख 22 हजार 792 बालक तथा 2 लाख 66 हजार 41 बालिकाएं हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बालिकाओं के बढ़ते प्रतिशत पर संतोष व्यक्त किया। लेकिन इस अवसर पर उन्होने राज्य में बालिकाओं के अपेक्षाकृत कम लिंगानुपात पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षक समुदाय को इस दिशा में समाज को जागृत करने हेतु आगे आना होगा। उन्होने कई स्कूलों में एक भी विद्यार्थी न होने और कई स्कूलों में दस से भी कम विद्यार्थी होने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए विद्यालयों की क्लबिंग का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों की क्लबिंग करके हम शिक्षकों तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते है।

मुख्यमंत्री ने शिक्षक संगठनों से भी अपील की कि वे सरकार और समाज को अपना रचनात्मक सहयोग दें। सरकार सभी शिक्षक संगठनों का सम्मान करती है, और उनकी सभी मांगो एवं सुझावों हेतु संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने शिक्षक समुदाय के चुनाव, जनगणना जैसी विभिन्न लोक कल्याणकारी गतिविधियों में दिये जा रहे योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य में ''आधार योजना'' और तकनीकि के विस्तार से इन अतिरिक्त कार्यों में कमी आयेगी। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आगे आकर अपनी बात रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होने कहा कि शीघ्र ही वे उलहवअण्पद के उत्तराखण्ड चैप्टर पर अपने सुझाव दे सकते हैं। साथ ही वे बउ.नं/दपबण्पद पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी 13 जनपदों के शिक्षकों को सम्बोधित किया। इस वीडियो कान्फ्रेंसिंग में जनपद, ब्लाक और तहसील के 114 स्वान सेन्टर, 94 कामन सर्विस सेन्टर, 13 जिला डायट केन्द्र तथा 13 जिला एन0आई0सी0 केंद्र जुड़े हुए थे'। इस वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों के शिक्षक भी सीधे जुड़े हुए थे। सचिवालय स्थित कान्फ्रेंसिंग कक्ष में मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव डा0 रणवीर सिंह, शिक्षा सचिव चन्द्रशेखर भट्ट, सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।